पेज 04 में...
हर जिले में चलेगी
इमरजेंसी डायल-112

साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 18 मई से 24 मई 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 12 में...
दिग्गजों से
हनीमून खत्म...

वर्ष : 02 अंक : 11 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 04 हाथ में बंदूक, दिल में सत्ता का रसूख, पुलिस बनी चौकीदार!

नवाचार ने किया निहाल...

जिला प्रशासन के नवाचार की नई राह से जिंदगी आसान

- 23 अभिनव प्रोजेक्ट्स बदल रहे हैं जनजीवन की तस्वीर
- कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुके लांच
- सबसे कम छुट्टियां लेने वाले रायपुर कलेक्टर हैं गौरव सिंह
- रायपुर पहला जिला जहां जनदर्शन सप्ताह में पांचों दिन

नीतियां जब कागजों से निकलकर सीधे जनता के सरोकार से जुड़ती हैं, तो बदलाव की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में तकनीक, संवेदनशीलता और सुशासन के तालमेल से एक ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। लोगों को सुविधा पहुंचाने और समस्या के निराकरण के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके हैं। जिले में इस वक्त करीब दो दर्जन ऐसे अनूठे अभियान चल रहे हैं, जो न केवल सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली को आधुनिक बना रहे हैं, बल्कि समाज के हर तबके को आत्मनिर्भरता का एक नया मंच भी दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह बदलने वाले इन अनूठे कलेक्टिव इनिशिएटिव्स पर पेश है प्रदीप चंद्रवंशी/विकास यादव की एक खास रिपोर्ट...

शहर सत्ता/रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा जनहित, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई अनूठे और प्रभावी नवाचार (इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट्स) चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा-निर्देशों और जिला प्रशासन के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर लागू किए गए ये प्रोजेक्ट्स न केवल आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहे हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त भी बना रहे हैं। रायपुर जिला प्रशासन के ये 23 प्रोजेक्ट्स इस बात का जीवंत उदाहरण हैं कि अगर सही विज़न और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए, तो सरकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक न सिर्फ पहुंचती हैं बल्कि उनके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं। डॉ. गौरव सिंह द्वारा रायपुर में की गई प्रशासनिक सुधार का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई हैं। उनके नेतृत्व में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई, जिससे आम जनता का विश्वास बढ़ा है। जनसुनवाई और विशेष अभियानों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया, वहीं डिजिटल तकनीक के उपयोग से सरकारी कामकाज को तेज, सरल और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर देते हुए विभिन्न विकास कार्यों को गति दी गई, जिससे समग्र रूप से रायपुर में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और जनहितकारी बनी है। इए डालते हैं जिला प्रशासन द्वारा संचालित इन सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर शहर सत्ता साप्ताहिक समाचार पत्र की एक विस्तृत नज़र

1 महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका के बढ़ते कदम

प्रोजेक्ट पिंक दीदी: नवा रायपुर में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। इसके तहत महिलाओं को 30 से अधिक ई-ऑटो दिए गए हैं। इससे जुड़कर महिलाएं प्रति माह 30 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।

प्रोजेक्ट अजा: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों से निर्मित पिंजड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं और 'पशु सखी कैडर' का गठन किया गया है। इस बेहतरीन मॉडल को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है।

2 शिक्षा और बच्चों के भविष्य को नई दिशा

प्रोजेक्ट यू-शेप (U-Shape): क्लासरूम के पारंपरिक ब्लैकबोर्ड-केंद्रित ढर्रे को बदलते हुए जिला प्रशासन ने 'Project U-Shape' शुरू किया है। इस छात्र-केंद्रित मॉडल में बच्चे अंग्रेजी अक्षर 'U' के आकार में बैठते हैं, जिससे हर छात्र शिक्षक की सीधी नजर में रहता है और सक्रिय अधिगम (Active Learning) को बढ़ावा मिलता है।

प्रोजेक्ट अनुभव: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे युवाओं के हौसले को नई उड़ान देने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें 'इंटरव्यू (साक्षात्कार) पूर्व प्रशिक्षण' दिया जा रहा है।

प्रोजेक्ट रचना: छात्रों की रचनात्मकता को निखारने और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह नगर निगम रायपुर और आईटीआई सड्डू का एक संयुक्त अनूठा प्रयास है। इसमें पुराने फ्लेक्स और बैनर का पुनर्चक्रण (Recycle) कर विद्यार्थी चटाइयाँ, बोतल कवर, कैरी बैग, और कंप्यूटर/सिलाई मशीन कवर जैसी उपयोगी चीजें बना रहे हैं।

प्रोजेक्ट अंतरिक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं IDYM फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में छात्रों के भीतर अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत नवा रायपुर के राखी में छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है।

3 स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा की गारंटी

प्रोजेक्ट धड़कन: बच्चों में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) के मुफ्त इलाज के लिए यह एक बेहद संवेदनशील पहल है। श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के सहयोग से स्कूलों और आंगनबाड़ियों में विशेष स्टेथोस्कोप के जरिए अब तक 98 हजार बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, और लक्षण पाए जाने पर उनका निशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है।

प्रोजेक्ट जिंदगी मुस्कुराएगी: कटे-फटे होंठ, तालू और विकृत हाथ-पैर की समस्या से पीड़ित बच्चों के लिए यह योजना नई जिंदगी लेकर आई है। इसके तहत प्रभावित बच्चों का पूरी तरह से निःशुल्क उपचार कराया जाता है।

प्रोजेक्ट छांव: शासकीय सेवकों की सेहत का ख्याल रखने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत अवकाश के दिनों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाकर सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है और मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं।

प्रोजेक्ट सुरक्षा: जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी, रायपुर के संयुक्त प्रयास से शासकीय कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सीपीआर (CPR) तथा अन्य आपदा प्रबंधन से जुड़ी चिकित्सीय सुविधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

5 सामाजिक सरोकार, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग कल्याण

प्रोजेक्ट आओ बांटें खुशियां: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 'न्योता भोज' को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शासकीय कर्मचारी और आम नागरिक अपने या परिजनों के जन्मदिन व खास अवसरों को आंगनबाड़ी और स्कूलों के बच्चों के साथ मनाते हैं, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं।

प्रोजेक्ट सहारा: वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष चिन्हांकन शिविर लगाए जाते हैं। यहाँ उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण और प्रमाण पत्र वितरित कर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।

प्रोजेक्ट दिव्य धुन: इस भावुक पहल के जरिए दिव्यांग बच्चों को कला केंद्रों में प्रशिक्षित कर एक म्यूजिकल बैंड का रूप दिया गया है। 'दिव्य धुन' बैंड ने राज्योत्सव सहित कई बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां देकर न केवल वाहवाही लूटी है, बल्कि अच्छी आय भी अर्जित की है।

प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग: सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के तहत उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को ही उनके सभी स्वत्वों (Dues) का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

4 सुशासन, त्वरित सेवा और जन-सुविधाएं

कॉल सेंटर (24/7): आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

प्रोजेक्ट वाटर फॉर ऑल: मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'निःशुल्क शुद्ध पेयजल हर नागरिक का अधिकार' अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों, और कैफे में आने वाले ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

टीम प्रहरी: रायपुर शहर की सड़कों पर सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के लिए 'टीम प्रहरी' मुस्तैद है। इसमें नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग के कुल 70 सदस्य शामिल हैं, जो रोजाना अतिक्रमण हटाने, अवैध प्लॉटिंग रोकने और यातायात को सुव्यवस्थित करने की कार्रवाई करते हैं।

प्रोजेक्ट झरिया: ग्राम पछेड़ा में स्थित झरिया एल्कलाइन वाटर प्लांट से 'झरिया' ब्रांड का शुद्ध एल्कलाइन पानी अब मंत्रालय, जंगल सफारी, आईआईएम, आईआईटी, कलेक्ट्रेट सहित राज्य के सभी प्रमुख शासकीय संस्थानों में नियमित रूप से सप्लाई किया जा रहा है। राज्योत्सव और खेलो इंडिया जैसे बड़े आयोजनों में भी इसकी सफल सप्लाई की गई।

6 कृषि, डिजिटल साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण

प्रोजेक्ट नैनो: किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने के लिए ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो डीएपी (DAP) और नैनो यूरिया के छिड़काव को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 10 हजार रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। किसान अधिकतम 20 बोतलें खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें 2 लाख रुपये का संकटहरण बीमा सुरक्षा कवच मिलता है, जिसका प्रीमियम इफ्को (IFFCO) वहन करता है।

प्रोजेक्ट दक्ष: शासकीय कार्यप्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों को कंप्यूटर, मोबाइल टूल्स, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और ई-मेल प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रोजेक्ट पाई-पाई: आम नागरिकों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों में वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इसके तहत लोगों को वित्तीय प्रबंधन, बचत की आदत, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल लेन-देन के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट मेरा गांव, मेरी पहचान: इस परियोजना के तहत जिले के 80 से अधिक गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव के लिए विभागीय अधिकारियों को क्रियान्वयन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना है।

प्रोजेक्ट ग्रीन पालना: पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का यह एक अनोखा उदाहरण है। इस अभियान के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव (डिलीवरी) के उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जाते हैं, ताकि घर में आई नई जिंदगी के आगमन के साथ धरती पर भी एक नए वृक्ष का जन्म हो।

ऐसे ही नहीं बनते 'गौरव'

गौरव सिंह का जन्म 1 जनवरी 1984 को उत्तरप्रदेश राज्य के हरदोई जिले के देवमनपुर गांव के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। पिता श्री शिवराज सिंह राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षक है। माता भी उच्च शिक्षित हैं। वे गृहणी हैं। गौरव सिंह ने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है। यूपीएससी भी गौरव सिंह ने हिंदी माध्यम से दिलाई थी। बारहवीं कक्षा गौरव सिंह ने गणित, भौतिकी, व रसायन विषयों के साथ उत्तीर्ण की। फिर उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर एनआईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक किया। बीटेक के बाद गेट निकाल कर दिल्ली आईआईटी से एमटेक किया। एमटेक के दौरान जर्मनी की प्रतिष्ठित कंपनी की फेलोशिप भी मिली। एमटेक के बाद पीएचडी भी पूरी की। फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। गौरव सिंह का मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य विषय की पढ़ाई गौरव सिंह ने मात्र लगभग 35 दिन में की। यूपीएससी में तीसरे प्रयास में सलेक्शन हुआ और वो आईएएस बने। 2012 में यूपीएससी में हिंदी साहित्य विषय में देश में सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए थे। फील्ड पोस्टिंग के लिए सहायक कलेक्टर के रूप में गौरव सिंह को रायगढ़ पोस्टिंग मिली। रायगढ़ के बाद महासमुंद जिले के सरायपाली में एसडीएम रहें। फिर दंतेवाड़ा जिला पंचायत सीईओ रहें। दंतेवाड़ा में जिला पंचायत में करीबन ढ़ाई साल सीईओ रहने के दौरान उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर्यटन को लेकर काफी काम किया। महिला समूहों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्री खोली। नक्सल इलाके के बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने प्रदेश का पहला बीपीओ कॉल सेंटर खोला। पालनार को कैशलेश विलेज बनाया। नक्सली ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास बनवाएं। नक्सल प्रभावित जिले में बेहतर काम के चलते गौरव सिंह को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड सहित चार नेशनल अवार्ड भी मिले। दंतेवाड़ा के बाद गौरव सिंह धमतरी, दुर्ग,रायपुर जिला पंचायत सीईओ भी रहें। सूरजपुर,मुंगेली, बालोद, जिले के कलेक्टर रहें। मुंगेली में 2 माह के छोटे कार्यकाल में ही 100 ग्रामों में चौपाल लगा जनता की समस्या सुलझाई। वर्तमान में गौरव सिंह राजधानी रायपुर के कलेक्टर हैं।

मील का पत्थर साबित हुए ये प्रयास

महिला समूहों को रोजगार देने गारमेंट फैक्ट्री खोलने, पालनार को कैशलेज ट्रांजेक्शन विलेज बनाने, नक्सल इलाके के बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने, प्रदेश का पहला बीपीओ कॉल सेंटर दंतेवाड़ा में खोलने, महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देकर उपलब्ध कराने जैसे कई क्षेत्रों में समाज कल्याण, सुधार के लिए सतत् कार्य करने वाले बेहतरीन कलेक्टरों में शामिल हो गए हैं गौरव सिंह।

50 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑनलाइन, महिलाओं व बच्चों को लाभ

लोगों को सुविधा पहुंचाने और समस्या के निराकरण के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके हैं। इसमें कई प्रोजेक्ट इतने कारगर साबित हुए हैं कि इनमें लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन मॉनीटरिंग सही तरीके से हो सके, इसमें गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मोड पर लाया जा रहा है। वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट जैसे 'धड़कन' में 18 साल के बच्चे के दिल से संबंधित जांच की जा रही है। अब तक स्कूलों के 2560 बच्चों की जांच की जा चुकी है, इनमें 14 बच्चे सस्पेक्टेड हैं, जिनका इलाज श्री सत्य साई अस्पताल में कराया जाएगा। घंटी प्रोजेक्ट में 1427 स्कूलों में शुरू हुआ है, जिसमें दो बार घंटी बजती है और सभी बच्चे पानी पीते हैं। इससे पानी की कमी से होने वाले बीमारी से बच्चों को बचा सके। प्रोजेक्ट का सुचारू रूप से चलाना, गड़बड़ी न होना, अधिकारियों की लापरवाही और सही समय में डाटा मिलना यह सभी काम ऑनलाइन मोड पर होने से मॉनीटरिंग सही ढंग से हो पाएगी। इसलिए ऑनलाइन मोड में लाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरु कर दी है। सभी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मोड पर लाया गया है।

30 अधिकारियों की टीम करती है नाम चयन

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि हमलोगों ने 25 से 30 अधिकारियों की टीम बनाई है जो कि सभी प्रोजेक्ट के नाम रखती है। इसमें वे अधिकारी शामिल है, जो इसमें समय देकर कुछ करना चाहते हैं। चर्चा कर समझते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, उसके बाद उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसमें सभी नाम बताते हैं, फिर उसमें से लोगों को कनेक्ट हो उस तरह के नाम का चयन कर रखा जाता है।

नए प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना

एक माह में और भी प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है। इसमें रक्षा- जो कि सर्वाइकल कैंसर के इलाज संबंधित कार्य किया जाएगा। इसमें 56000 हजार से ज्यादा महिलाएं इसकी चपेट में है। वहीं, पढ़े रायपुर, बढ़े रायपुर प्रोजेक्ट में 1-8वीं तक बच्चों को बोर्ड पढ़ाई में गुणवत्ता, इनोवेटिव ऐप से पढ़ाई। प्रोजेक्ट पल्स, रक्षा, गोल्डन ऑवर, मिशन 45, आंगन, हैंडी, जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे।

इस तरह के चल रहे प्रोजेक्ट

- **यू आकार:** बच्चों को बैक बैंचर वाली फीलिंग न आए, इसलिए उन्हें 932 स्कूल में यू आकार में बैठाया जा रहा है
- **उत्कर्ष:** 10वीं-12वीं के छात्राओं का रिजल्ट अच्छा करने बार-बार टेस्ट, 215 स्कूल शामिल
- **विजयीभव:** अलग-अलग विभाग के लोग बच्चों को गुड-बैड टच, साइबर व नशा मुक्ति की शिक्षा दे रहे हैं।
- **सुरक्षा:** छात्राओं को प्राथमिक उपचार और सीपीआर की ट्रेनिंग
- **दधिचि:** लोगों को अंगदान करने के लिए जागरुकता, अब तक 27 लोगों ने किया
- **हरिहर पाठशाला:** वृहद स्तर पर पौधारोपण के साथ उसकी रक्षा, अबतक हजारों पौधरोपण हुए
- **दक्ष:** अधिकारी-कर्मचारियों को डिजिटल रूप से मजबूत करने प्रशिक्षण
- **स्मृति पुस्तकालय:** छात्राओं के पढ़ने के लिए पुस्तकों का दान
- **नैनो:** ड्रोन तकनीक से उर्वरकों के छिड़काव का निरीक्षण

शिक्षा में पिछड़ रहा छत्तीसगढ़

प्रदेश में ड्रॉपआउट दर 15.3%, ये राष्ट्रीय औसत से 3.8% कम

रायपुर। राज्य माध्यमिक स्तर पर बढ़ते ड्रॉपआउट, हजारों एकल शिक्षक स्कूल, शिक्षकों के रिक्त पद, डिजिटल सुविधाओं की कमी और कमजोर सीखने के परिणाम जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थिति राष्ट्रीय औसत के आसपास है, लेकिन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ काफी पीछे दिखाई देता है। यह खुलासा नीति आयोग की 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया: टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप' नामक रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की कई कमजोर कड़ियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट का दर 15.3% दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.5% है। यानी छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से 3.8% पीछे है। इसका मतलब यह है कि हर 100 में लगभग 15 छात्र माध्यमिक स्तर तक पहुंचने से पहले पढ़ाई छोड़ रहे हैं। 9वीं-10वीं के दौरान स्कूल छोड़ने वाले छात्र आगे उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की मुख्यधारा से बाहर हो जाते हैं।

पढ़ाई छोड़ने के प्रमुख कारणों में आर्थिक कारण, दूरस्थ स्कूल, परिवहन की कमी और कमजोर शैक्षणिक वातावरण माने जा रहे हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो केरल, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्यों ने ड्रॉपआउट को काफी हद तक नियंत्रित किया है, जबकि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की स्थिति देश में सबसे खराब बनी हुई है। रिपोर्ट में शिक्षा और उसके स्तर को लेकर कई बातों का जिक्र है।

ड्रॉपआउट दर: शीर्ष वाले और निचले स्तर के राज्य

बेहतर राज्य	ड्रॉपआउट	कमजोर राज्य	ड्रॉपआउट
चंडीगढ़	2.0%	पश्चिम बंगाल	20.0%
झारखंड	3.5%	कर्नाटक	18.3%
लक्षद्वीप	4.1%	अरुणाचल प्रदेश	18.3%
उत्तराखंड	4.6%	असम	17.5%
केरल	4.8%	मेघालय/मिजोरम	17.4%

समस्या : 5973 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

राज्य में 5,973 स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक पदस्थ है। इन स्कूलों में 2.13 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिक्षक को पढ़ाई के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जिससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित होती है।

देश में स्थिति

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति इससे भी खराब है, लेकिन केरल, दिल्ली और कई केंद्र शासित प्रदेशों ने लगभग शून्य एकल शिक्षक स्कूल का मॉडल हासिल कर लिया है।

म्यूल अकाउंट केस:475 आरोपी दो साल से जेल में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

रायपुर। म्यूल अकाउंट से जुड़े साइबर फ्रॉड मामलों में रायपुर सेंट्रल जेल में पिछले दो साल से बंद 475 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने ऐसे मामलों में जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्यारे को सुधारा जा सकता है, लेकिन साइबर अपराधियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद निचली अदालतों में भी सख्ती बढ़ गई है। इस वजह से कोई भी अदालत इस तरह के आरोपियों को जमानत नहीं दे रही है। रेंज साइबर पुलिस के अनुसार मार्च 2024 से म्यूल अकाउंट के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था, जो पिछले साल तक चला। इस दौरान खाते और फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले और बैंक अधिकारियों तक पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिकाएं लगाई, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली।

10 से 25 हजार में बेचे बैंक खाते

जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश आरोपियों ने अपने बैंक खाते 10 से 25 हजार रुपए में बेच दिए थे। कुछ आरोपी हर महीने कमीशन भी ले रहे थे। आरोपियों ने जानबूझकर अपने खाते और सिम कार्ड ठगों को सौंप दिए। इन खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया गया। रायपुर में ऐसे 3000 खातों में ठगी की रकम जमा कराई गई। ये सभी म्यूल अकाउंट हैं। सब्जी, फल और दूध बेचने वालों के नाम पर खाते खोलकर उनमें रोजाना करोड़ों का लेन-देन किया जा रहा था।

RTE विवाद के बीच निजी स्कूल 18 मई से फिर देंगे एडमिशन

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा- गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश को लेकर बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। संगठन ने घोषणा की है कि 18 मई से प्रदेश के सभी निजी स्कूल फिर से RTE के तहत प्रवेश देना शुरू करेंगे। हालांकि, प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने और एंट्री क्लास बदलने के विरोध में चल रहा असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। निजी स्कूल संचालकों ने 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन की अगली कड़ी में 4 अप्रैल को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इस साल RTE के तहत प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया गया था। संगठन का आरोप है कि लगातार मांगों की अनदेखी की जा रही है। संगठन के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी हालिया आंकड़ों में 33 में से 29 जिलों में 50% से अधिक सीटें खाली रहना आंदोलन की सफलता को दर्शाता है।

हाईकोर्ट में लंबित है मामला

संगठन ने प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका क्रमांक WPC 4988/2025 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग को छह महीने के भीतर संगठन की रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। संगठन का आरोप है कि आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। संगठन ने कहा कि आंदोलन अब केवल प्रतिपूर्ति राशि तक सीमित नहीं है। इस वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों में RTE की एंट्री क्लास बदलकर पहली कक्षा कर दी है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि इससे वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है।

रायपुर में डेयरी फैक्ट्री पर चला बुलडोजर

सड्डू में 1.45 एकड़ सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

रायपुर। रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने सड्डू इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदन डेयरी फैक्ट्री द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम जोन-9 के वार्ड क्रमांक 8 में फैक्ट्री पर करीब 1.45 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन और श्रमिकों की मदद से अभियान चलाकर अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की अवैध बाउंड्रीवाल और शेड को हटा दिया गया। वहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए बनाए गए अवैध शेड को भी तोड़ा जा रहा है।

यह कार्रवाई रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। मौके पर रायपुर तहसीलदार राममूर्ति दीवान की मौजूदगी में पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम जोन-9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब और उप अभियंता आशुतोष पांडे समेत निगम के कई अधिकारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

रायपुर में 10%, रायगढ़ में 4.65% और भिलाई नगर में 7.84% हुआ काम, आदिवासी और ग्रामीण जिले आगे

जनगणना में पिछड़े रायपुर-दुर्ग-रायगढ़ समेत शहरी जिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियां चल रही हैं। राज्यभर में मकान सूचीकरण ब्लॉकों (HLB) के गठन और सत्यापन का काम चल रहा है। जिसमें बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य सरकार की ताजा प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 60.73% काम पूरा हो चुका है। कुल 48,742 मकान सूचीकरण ब्लॉकों में से 29,602 ब्लॉकों का सत्यापन और गठन पूरा कर लिया गया है। हालांकि राजधानी रायपुर, रायगढ़, दुर्ग-भिलाई जैसे शहरी जिले इस अभियान में काफी पीछे चल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम सबसे निचले पायदान पर है, जहां सिर्फ 4.65% काम ही पूरा हो पाया है। वहीं भिलाई नगर में 7.84% और रिसाली में 8.33% कार्य पूरा हुआ है। राजधानी रायपुर की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। यहां कुल 1,964 ब्लॉकों में से सिर्फ 203 ब्लॉकों का काम पूरा हो पाया है, यानी महज 10.34% प्रगति दर्ज हुई है। हां शहरी इलाके पिछड़ रहे हैं, वहीं आदिवासी और ग्रामीण जिलों ने जनगणना तैयारियों में बाजी मार ली है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिला 100% काम पूरा कर राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा

जशपुर में 99.87% और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 99.84% काम पूरा हो चुका है। बेमेतरा में 97.8% और मुंगेली में 96.52% प्रगति दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री बोले- सटीक जनगणना से पहुंचेगा सुशासन

मुख्यमंत्री साय ने जनगणना कार्य की प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना 2027 के आंकड़े भविष्य की योजनाओं, विकास और जनकल्याणकारी नीतियों की मजबूत नींव बनेंगे। मुख्यमंत्री ने बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को मैदानी मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

माइक्रो प्लानिंग से GPM बना नंबर-1

GPM कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने जिले की सफलता का श्रेय स्थानीय प्रगणकों और प्रशासनिक टीम को दिया। उन्होंने बताया कि दुर्गम और आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद माइक्रो प्लानिंग और रोजाना डिजिटल मॉनिटरिंग की मदद से 100% लक्ष्य हासिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में "HLBs Not Started" का आंकड़ा शून्य है। यानी लगभग सभी जगह मैदानी स्तर पर काम शुरू हो चुका है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

हर जिले में चलेगी इमरजेंसी डायल-112 शाह हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना

जनसुविधा और नीतिगत बैठकों पर फोकस

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 मई की रात करीब 8 बजे रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे के दौरान वे सुरक्षा व्यवस्था, जनसुविधाओं के विस्तार और उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह 18 मई को सुबह 10:15 बजे रायपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड से राज्य की आपातकालीन सेवा डायल-112 के नए आधुनिक 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अभी तक 16 जिलों में ही यह सुविधा थी। अब 33 जिलों में होगी। इसके बाद वे बस्तर के नेतानार पहुंचेंगे, जहां सुबह 11:45 बजे जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे।

इसका उद्देश्य सुदूर अंचलों में शासकीय और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। दोपहर 1 बजे शाह जगदलपुर स्थित अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे बादल अकादमी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शहीद परिवारों, विशेष सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल पीड़ितों और स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। शाम 6:30 बजे वे 'बस्तर के संग' लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल बैठक में सीएम योगी, धामी और यादव होंगे शामिल जगदलपुर में मंगलवार को पहली बार 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी और एमपी के सीएम मोहन यादव शामिल होंगे।

देश को 2700 किलो सोना देगा छत्तीसगढ़:बलौदाबाजार के बाघमारा में देश की चौथी गोल्ड माइंस

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे एक साल तक सोना न खरीदें। इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए को कमजोर होने से बचाना है। भारत में सोने का भंडार कम है और देश लगभग 90% सोना दूसरे देशों से आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर बड़ा दबाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ इस बोझ को कम करने में मदद करेगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के बाघमारा में देश की चौथी गोल्ड माइंस है। यहां ड्रिलिंग में सोने के कण मिले हैं। अगले 2 साल में खनन भी शुरू हो जाएगा। इस खदान से 2700 किलो सोना निकलने की उम्मीद है, इससे सरकार को 81.4 करोड़ रुपए की आय होगी। यहां पर पहाड़ के नजदीक घने जंगल के बीचोंबीच एक्सप्लोरेशन का काम जारी है।

20 मई को केमिस्ट हड़ताल, कई मेडिकल स्टोर्स रहेंगे बंद

रायपुर। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों ने 20 मई 2026 को देशभर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य में जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा है कि आम नागरिकों और मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राज्य के सभी जिलों में अधिकारियों को जीवनरक्षक दवाओं, आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पादों और चिकित्सकीय सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शासकीय जनऔषधि केंद्रों, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स, सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और अन्य दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

जनऔषधि केंद्रों और अस्पतालों को दवा और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के निर्देश

केमिस्ट एसोसिएशन से सहयोग की अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने छत्तीसगढ़ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन को भी पत्र भेजकर अपील की है कि विरोध कार्यक्रम के दौरान जनहित और मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

अनावश्यक दवाओं का संग्रह न करें

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर अनावश्यक दवाओं का संग्रह न करें। जिन मरीजों को नियमित दवाएं लेनी होती हैं, वे डॉक्टर की सलाह के अनुसार आवश्यक दवाएं पहले से लेकर रखें। आपात स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जनऔषधि केंद्रों और अन्य उपलब्ध मेडिकल स्टोर्स से दवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

1952 में घासीदास संग्रहालय से चोरी हुई 'अवलोकितेश्वर' की प्रतिमा वापस लाई जाएगी

रायपुर। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से चुराई गई 'अवलोकितेश्वर' की कांस्य प्रतिमा वापस छत्तीसगढ़ लाई जाएगी। इसे फिर से म्यूजियम में स्थापित की जाएगी। इसके लिए संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमा अब तक भारत नहीं पहुंची है।

प्रतिमा के भारत पहुंचने के बाद खुद संस्कृति मंत्री रिसीव करने दिल्ली जाएंगे। दरअसल, अमेरिका ने भारत को करीब 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। इन वस्तुओं में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से चुराई गई करीब 19 करोड़ की 'अवलोकितेश्वर' की कांस्य प्रतिमा भी है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की दूत राजलक्ष्मी कदम की मौजूदगी में भारत को सौंपा गया है।

सिरपुर से मिली थी प्रतिमा प्रतिमा वर्ष 1939 में लक्ष्मण मंदिर के पास मिली कांस्य प्रतिमाओं के एक बड़े भंडार का हिस्सा थी। इसके बाद इसे रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के संग्रह में रखा गया। लेकिन 1982 के आसपास इसकी चोरी हो गई। चोरी की गई प्रतिमा अमेरिका तस्करी कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि शिलालेख में कारीगर का नाम द्रोणादित्य अंकित है, जो महासमुंद जिले के श्रीपुर (वर्तमान में सिरपुर) के निवासी थे।

जेईई एडवांस 2026 परीक्षा स्टूडेंट्स में दिखा उत्साह, 1 जून को जारी हो सकता है रिजल्ट

रायपुर। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस 2026 रविवार 17 मई को संपन्न हो गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश का सपना देखने वाले छत्तीसगढ़ के हजारों छात्र-छात्राएं रायपुर, भिलाई और बिलासपुर के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने पहुंचे। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी रुड़की की ओर से किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर करीब ढाई लाख विद्यार्थियों को जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना गया था। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और परीक्षा आयोजित करने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राज्यवार आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं करते हैं, लेकिन पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी लगभग 2 से 3 प्रतिशत मानी जाती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ से करीब 5 हजार से 7 हजार 500 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस के लिए पात्रता हासिल की। इनमें रायपुर, भिलाई, बिलासपुर समेत प्रदेश के कई शहरों के विद्यार्थी शामिल हैं।

दो चरणों में हुई परीक्षा

जेईई एडवांस 2026 का पहला प्रश्नपत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा प्रश्नपत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया गया। दोनों प्रश्नपत्रों में शामिल होना अनिवार्य था। परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि भौतिक विज्ञान और गणित अपेक्षाकृत कठिन रहे, जबकि रसायन विज्ञान संतुलित रहा।

परीक्षा केंद्रों के बाहर दिखी भीड़

रायपुर, भिलाई और बिलासपुर के परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभिभावकों और विद्यार्थियों की भीड़ लगी रही। सुरक्षा व्यवस्था के बीच विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर प्रवेश दिया गया। कई अभिभावक गर्मी के बावजूद घंटों तक केंद्रों के बाहर इंतजार करते नजर आए। जेईई एडवांस 2026 का परिणाम 1 जून 2026 को जारी होने की संभावना है। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को देश के शीर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश मिलेगा।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

हाशिये पर मुस्लिम

मुस्लिम देशों (पाकिस्तान को छोड़कर) के मुसलमानों और मुस्लिम नेताओं से हम गलबहियां पा रहे हैं। तो भारतीय मुसलमानों से आखिर कोफ़्त क्यों? सवाल उठने लगा है कि 'क्या मुसलमान भाजपा के लिए कोई अहमियत रखते हैं?' हाल के राज्यों के चुनाव नतीजे- खासकर बंगाल और असम के- जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 30% से ज्यादा है- दिखाते हैं कि यह मुद्दा अब और बड़ा हो गया है। राजनीतिक तौर पर तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मुसलमान आज भाजपा के लिए 2019 के मुकाबले काफी कम मायने रखते हैं। बंगाल और असम में भाजपा ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे बिना दो-तिहाई सीटें जीत लीं। दूसरी तरफ, असम में विपक्ष के जीते 24 उम्मीदवारों में से 22 मुस्लिम हैं। इनमें भी कांग्रेस के 19 जीते उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं। बंगाल में 293 नए विधायकों में 40 मुस्लिम हैं, जिनमें से 34 टीएमसी के हैं।

यानी टीएमसी के कुल 80 जीते उम्मीदवारों में से 45 फीसदी मुस्लिम हैं। इसका मतलब यह है कि जिन दो राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है (जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं है), वहां मुसलमान सत्ता से बाहर हो चुके हैं। भाजपा और सेकुलर पार्टियों के बीच हिंदू-मुस्लिम आधार पर बंटवारा साफ हो गया है।

केरल में यूडीएफ के 102 नए विधायकों में 30 मुस्लिम और 29 ईसाई हैं। सेकुलर खेमे को इस बात से राहत हो सकती है कि कम से कम केरल में मुसलमान सत्ता में शामिल हैं, लेकिन यह राहत इस डर से कम हो जाती है कि भाजपा अब इसे अल्पसंख्यकों की सरकार बताकर हिंदू वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 18वीं लोकसभा में कुल 24 मुस्लिम सांसद हैं, यानी सिर्फ 4.42 फीसदी, जबकि देश में मुस्लिम वोटरों की आबादी 15 फीसदी से ज्यादा है। 16वीं लोकसभा में 22 और 17वीं लोकसभा में 27 मुस्लिम सांसद थे। जबकि 1980 में 49 और 1984 में 45 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। तब उनका प्रतिशत क्रमशः 9 और 8.3 था। लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या अकसर 5 फीसदी के आसपास रही है, लेकिन केंद्र में उन्हें हमेशा अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता रहा। यहां तक कि वाजपेयी सरकार में सिकंदर बख्त मंत्री थे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपसभापति जैसे पदों से लेकर सेना और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख पदों तक मुसलमान पहुंच चुके हैं, लेकिन आज वे किसी भी ऐसे पद पर नहीं हैं। आज कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। सिर्फ एक मुस्लिम राज्यपाल हैं- बिहार में सैयद अता हसनैन। केंद्र सरकार के करीब 100 सचिवों में सिर्फ एक मुस्लिम हैं- कामरान रिजवी- जो हैवी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सचिव हैं। सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों में भी सिर्फ एक मुस्लिम जज हैं- जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। भारत के आखिरी मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएम अहमदी थे, जो 24 मार्च 1997 को रिटायर हुए थे।

यह सब देखकर ऐसा लग सकता है कि भारतीय मुसलमानों से भाजपा किनाराकश कर रही है, लेकिन इस सोच पर फिर से विचार करने की जरूरत है। डॉक्टरी, कानून, शिक्षा, विज्ञान, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, मनोरंजन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। सिविल सेवा और सेना में भी उनका चयन बढ़ा है। इसलिए समस्या यह नहीं है कि मुसलमान हर क्षेत्र से बाहर हो रहे हैं। असली समस्या यह है कि राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। भारतीय राजनीति के विरोधाभास स्पष्ट हैं। एक तरफ लोकतंत्र की जीत हो रही है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मैदान को छोटा करने की कोशिश होती है। एक जगह धार्मिक विविधता है, तो दूसरी जगह उस पर हमला भी सफल रहता है।

1996 में वाजपेयी सरकार 13 दिन चली थी और 1999 में एक वोट से गिर गई थी। तब भाजपा नेता बलबीर पुंज इस बात से नाराज थे कि मुस्लिम वोटों पर निर्भर पार्टियां भाजपा को स्वीकार नहीं कर रही थीं। उनका मानना था कि मुसलमान तय कर रहे थे भारत पर कौन राज करेगा और कौन नहीं, लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है।

ये तथ्य तीन बड़े निष्कर्षों की ओर इशारा करते हैं। एक, भाजपा की विरोधी या सेकुलर पार्टियों को भाजपा अब मुस्लिम पार्टियों की तरह पेश करना चाहती है, जबकि उनके नेता हिंदू हैं। इससे हिंदू बनाम बाकी सब वाला माहौल बनता है, जो 80 फीसदी बनाम 20 फीसदी की राजनीति में बदल जाता है।

यह भाजपा के लिए सबसे फायदेमंद स्थिति है। तुर्रा यह कि अब भी कुछ सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोटों पर निर्भर हैं, लेकिन वे इतनी सतर्क हो गई हैं कि मुसलमानों के समर्थन में खुलकर बोलने से भी बचती हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने शाहीन बाग आंदोलन और उसके बाद हुए दंगों के दौरान चुप्पी बनाए रखी। इससे धर्मनिरपेक्षता बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर आ गई है। यह न सिर्फ मुश्किल और अव्यावहारिक है, बल्कि गलत भी है। सनद रहे भारत के हिंदुओं ने ही संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को चुना था, इसलिए उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। भाजपा को वही चुनौती दे पाएगा, जो हिंदुओं के साथ भरोसे का रिश्ता बना सके। भाजपा के लिए मुस्लिम वोटर्स अब जरूरी नहीं रह गए हैं।

केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार होने से क्या होता है?

नीरज कौशल

हाल के सालों में भाजपा ने नियमित रूप से 'डबल इंजन सरकार' के नारे का इस्तेमाल किया है। लेकिन कानून के जानकारों का तर्क है कि यह नारा भारतीय शासन-व्यवस्था की संघीय संरचना को कमजोर करता है। इसमें यह संकेत निहित है कि केंद्र और राज्य में अगर अलग-अलग दलों की सरकारें हों तो यह बात राज्य की जनता के हित में नहीं होती। बेशक, इस नारे की विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की जा सकती हैं, लेकिन इसका प्रचलित अर्थ यही है कि जब केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टियों की विचारधारा अलग होती है, तब उनके बीच समन्वय कमजोर रहता है। इस नारे के व्यापक इस्तेमाल से दो प्रश्न उठते हैं।

पहला, क्या यह दावा सच है कि जिन राज्यों की जनता केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को चुनती है, वे कहीं अधिक तेज आर्थिक विकास और बेहतर शासन का अनुभव करते हैं? दूसरा, क्या इस नारे ने भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने में सफलता दिलाई है? पहले प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, और दूसरे का उत्तर कुछ चुनावों में 'हां' है। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और इसका उत्तर हाल के कुछ विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को पिछले वर्ष बिहार और इस वर्ष असम में दोबारा सत्ता मिली।

'डबल इंजन सरकार' के तर्क के अनुसार, दोनों राज्यों को तेज आर्थिक प्रगति के चमत्कार के रूप में उभरना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों राज्य देश की आर्थिक सीढ़ी में सबसे निचले पायदानों पर हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, जबकि बड़े राज्यों में असम की प्रति व्यक्ति आय चौथी सबसे कम है। सुप्रशासन के मामले में भी इन राज्यों को आदर्श नहीं माना जा सकता।

दूसरी ओर, भाजपा ने कभी भी केरल या तमिलनाडु में शासन नहीं किया है। 'डबल इंजन सरकार' के तर्क के अनुसार, दोनों राज्यों को आर्थिक रूप से बदहाल होना चाहिए था। इसके बिलकुल विपरीत, दोनों राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हैं और तमिलनाडु को सबसे बेहतर शासित राज्यों में से एक भी माना जाता है।

साथ ही, अकसर ऐसी रिपोर्टें सामने आती रही हैं कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भागीदारी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, बंगाल में तृणमूल के शासनकाल के दौरान राज्य को 2022 से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों से वंचित रखा गया। केंद्र ने व्यापक भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और केंद्रीय निर्देशों के अनुपालन में विफलता के आरोपों के आधार पर इन दोनों योजनाओं को रद्द कर दिया।

यद्यपि ये आरोप पूरी तरह असत्य नहीं हो सकते, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की अनियमितताओं के बावजूद फंड्स को निरस्त नहीं किया गया था। बंगाल में यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का संकेत देती है। इसी प्रकार, केंद्र ने तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा निधि में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक दी थी।

आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और पीएमश्री योजना का अनुपालन नहीं किया है। संक्षेप में, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से आर्थिक विकास तो नहीं होता, लेकिन केंद्र उन राज्यों के प्रति अधिक उदार रवैया अपनाता जरूर पाया जाता है, जहां उसकी अपनी पार्टी सत्ता में होती है। अब दूसरा सवाल। क्या यह नारा सत्तारूढ़ पार्टी को वोट दिलाता है?

लोकनीति-सीएसडीएस ने 2014 से 2022 के बीच 22 सर्वेक्षण किए, जिनमें उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे मानते हैं विकास के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी एक हो? 22 में से 5 सर्वेक्षणों में इस कथन से पूर्णतः असहमत उत्तरदाताओं की संख्या सहमत लोगों से अधिक थी; जबकि शेष 17 में इसका उलटा था। सर्वेक्षणों के समय चार राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दल सत्तारूढ़ थे।

लेकिन चुनावों के बाद भाजपा और उसके सहयोगी 12 राज्यों में सत्ता में आए। दो राज्यों में भाजपा सत्ता खो बैठी। लब्बोलुआब यह है कि यह नारा भाजपा को चुनाव जिताने में सहायक तो हो सकता है, लेकिन जो राज्य इस नारे का अनुसरण कर भाजपा को चुनते हैं, वहां इससे आर्थिक समृद्धि आने के प्रमाण नहीं हैं।

एनडीए को पिछले वर्ष बिहार और इस वर्ष असम में दोबारा सत्ता मिली। लेकिन ये दोनों राज्य देश की आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदानों पर हैं। वहीं केरल और तमिलनाडु प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

विवाह देह है, दाम्पत्य आत्मा है

इस समय लगभग हर क्षेत्र युद्धग्रस्त है। ट्रेड वॉर, टेक वॉर, लैंड वॉर, थॉट वॉर, जेनरेशन वॉर और सबसे खतरनाक फैमिली वॉर। हमारा विषय परिवार है। परिवार में भी युद्ध की स्थितियां बनती जा रही हैं। लोगों ने रिश्तों को हथियार बना लिया है। डिजिटल मीडिया ने भी परिवार के प्रेम पर आक्रमण किया है। ये इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है।

उन्होंने सिखाया कि डिजिटल बाजार से पैसा कैसे कमाया जाता है। अब परिवार बचाने के लिए भी हमें इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेनी चाहिए। देश में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग 2200 करोड़ रुपए के लगभग हो चुकी है। तो क्यों ना हम इन्फ्लुएंसर्स से मदद मांगें कि भारत के परिवार बचने चाहिए, इसकी प्रेरणा की भी वो मार्केटिंग करें।

विवाह को तो प्रोडक्ट बना ही दिया है। दीवाने हो गए लोग शादियों के आयोजन में, लेकिन दाम्पत्य को लेकर गम्भीर नहीं हैं। विवाह और दाम्पत्य में अंतर है। विवाह देह है और दाम्पत्य आत्मा है। इन्फ्लुएंसर्स यदि दाम्पत्य की जबर्दस्त मार्केटिंग कर दें तो परिवारों के ऊपर बड़ा उपकार होगा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका?

चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए संकेत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चीन दौरे से लौट आए. वापसी के साथ ही उनके सामने ईरान को लेकर बड़ा फैसला खड़ा हो गया है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अब अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है. अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों ने संभावित सैन्य कार्रवाई की नई योजना तैयार कर ली है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि कूटनीति पूरी तरह विफल हो गई है, तो अमेरिका जल्द ही ईरान पर फिर सैन्य हमले शुरू कर सकता है. बताया गया कि पेंटागन अधिकारी "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" को दोबारा शुरू करने की तैयारी में हैं. पिछले महीने ट्रंप द्वारा युद्धविराम घोषित किए जाने के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था.

अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतिम फैसला नहीं लिया है. बीजिंग से लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया. ट्रंप ने कहा, "मैंने प्रस्ताव देखा और अगर मुझे पहली लाइन ही पसंद नहीं आती, तो मैं उसे फेंक देता हूं."ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक में ईरान का मुद्दा उठा था. हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने चीन से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया.

चीन के लिए अहम है होर्मुज

रिपोर्ट के अनुसार चीन, ईरान का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और वह होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाली तेल और गैस आपूर्ति पर काफी निर्भर है. इसी वजह से कई देश इस संकट को खत्म करने और ईरान को दोबारा इस समुद्री मार्ग को खोलने के लिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं.

अमेरिका चाहता है कूटनीतिक जीत

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों के अधिकारी ऐसा समझौता कराने में जुटे हैं, जिससे ट्रंप इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर सकें. इसका उद्देश्य अमेरिकी मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना भी है कि अमेरिका किसी लंबे और महंगे युद्ध में नहीं फंसेगा. हालांकि हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस सप्ताह कांग्रेस में बयान देते हुए कहा, "जरूरत पड़ने पर हमारे पास संघर्ष बढ़ाने की योजना तैयार है." साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास सैन्य तैनाती कम करने और मध्य पूर्व में मौजूद 50 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धीरे-धीरे वापस बुलाने की योजना भी मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली अधिकारी अगले सप्ताह ईरान पर संभावित नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं. मध्य पूर्व के दो अधिकारियों ने इसे युद्धविराम लागू होने के बाद की "सबसे बड़ी तैयारी" बताया है.

डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की गुंजाइश नजर नहीं आती दिख रही है. दोनों देशों के बीच सीजफायर के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि शायद युद्ध समाप्ति को लेकर किसी तरह की बात बनेगी, हालांकि अब उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है. इधर, अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत फेल हुई तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं. ऐसे में जंग फिर से भड़क सकती है. मामला दोनों देशों के बीच पांच शर्तों को लेकर फंसा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युद्ध की चेतावनी दी है, जिसने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी नौसेना अधिकारी के साथ खड़े हैं. यह तस्वीर AI Generated है. दोनों एक वॉर शिप पर खड़े हैं. पीछे समुद्री लहरे उछाल मार रही हैं. तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है कि माहौल तनाव पूर्ण हैं. वहीं, एक ईरान का जहाज भी इसमें नजर आ रहा है. ट्रंप ने इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान से पहले की शांति. ऐसे में अब वैश्विक स्तर पर कयास लगाए जा रहे हैं, कि क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है? या किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है. साथ ही ट्रंप लगातार चेतावनी भी ईरान को लेकर जारी कर रहे हैं।

केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे शपथ

नई दिल्ली। केरल में यूडीएफ ने बहुमत हासिल किया, लेकिन सीएम के ऐलान में काफी समय लगा दिया. इससे

पहले गुरुवार यानी 14 मई को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगाई. अब उनके शपथ ग्रहण से जुड़ी जानकारी सामने आई है. खुद वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. केरल के मुख्यमंत्री पद नामित वीडी सतीशन का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे (18 मई 2026) होगा. मुख्यमंत्री के साथ-साथ लगभग 6 दशकों के बाद पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेगी. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के 63 विधायकों में कई काबिल नेता हैं. कई काबिल नेताओं को बाहर भी रखा गया है. वे कैबिनेट से बाहर ही रहेंगे. इसमें दुख और कठिनाई है. विभिन्न सीमाओं, मानदंडो और सामाजिक वास्तविकताओं के कारण ऐसे निर्णय लिए गए हैं.केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतात्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने 140 सीटों में से 102 सीटें जीतीं थीं.।

भारत के साथ पड़ोसी देशों में भी महंगी हुई पेट्रोल की धार

मिडिल ईस्ट के ताजा तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने से आज पूरी दुनिया भयंकर महंगाई से जूझ रही है. कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में दिख रहा है. भारत के साथ-साथ उसके तमाम पड़ोसी मुल्कों में भी ईंधन के दामों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है. सप्लाई संकट की वजह से म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में आम जनता पर खर्च का बोझ भारी हो गया है.

म्यांमार में भयंकर तेल संकट

भारत के इस पड़ोसी देश में ईंधन की कीमतों ने आसमान छू लिया है. वैश्विक तेल संकट और आंतरिक हालातों की वजह से म्यांमार में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं. आंकड़ों के मुताबिक, म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में 89.7 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं अगर डीजल की बात करें, तो इसके दाम 112.7 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन की दिक्कतों का सबसे बुरा असर इसी देश पर पड़ा है.

पाकिस्तान में ईंधन की रिकॉर्ड उछाल

कच्चे तेल की मार झेलने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के तमाम प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से यहां आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 54.9 प्रतिशत का तगड़ा उछाल आया है. इसके साथ ही डीजल की कीमतों में भी राहत नहीं है और वह भी 44.9 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है, जिसने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है.

भारत ने खारिज किया सिंधु जल संधि पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर हेग स्थित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के ताजा फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है. भारत ने साफ कहा है कि यह अदालत अवैध तरीके से गठित की गई है और इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है. इसलिए इसके किसी भी फैसले, आदेश या कार्रवाई को भारत मान्यता नहीं देता. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अवैध रूप से गठित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 15 मई 2026 को सिंधु जल संधि के तहत अधिकतम जल भंडारण क्षमतासे जुड़े मामले में एक तथाकथित फैसला जारी किया है. उन्होंने कहा कि भारत इस तथाकथित फैसले को पूरी तरह खारिज करता है, जैसे पहले दिए गए सभी फैसलों को खारिज किया गया था. भारत ने कभी भी इस अदालत के गठन को मान्यता नहीं दी. ऐसे में इस अदालत की किसी भी कार्यवाही, फैसले या आदेश का कोई कानूनी महत्व नहीं है।

ईबोला के अलग-अलग स्ट्रेन, लेकिन खतरा बरकरार

WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में तेजी से फैल रहे ईबोला वायरस को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है. यह संक्रमण बुंडीबुग्यो वायरस के कारण फैल रहा है, जो ईबोला वायरस का एक खतरनाक स्ट्रेन माना जाता है. यह स्ट्रेन पहले फैल चुके ज़ैरे स्ट्रेन से अलग है. बुंडीबुग्यो स्ट्रेन पहली बार साल 2007-2008 में युगांडा के बुंडीबुग्यो जिले में सामने आया था. उस समय इस वायरस ने 116 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था और करीब 34 से 40 प्रतिशत मरीजों की मौत हुई थी. अब डीआरसी के इटुरी प्रांत में 17वीं बार ईबोला का प्रकोप सामने आया है, लेकिन इस बार वायरस का प्रकार अलग होने से चिंता और बढ़ गई है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई विशेष वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है.

विशेषज्ञों के मुताबिक ईबोला वायरस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इंसानों में बड़े स्तर पर संक्रमण मुख्य रूप से ज़ैरे, सूडान और बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से फैलता है. ज़ैरे स्ट्रेन सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, जिसमें मृत्यु दर 60 से 90 प्रतिशत तक हो सकती है. वहीं बुंडीबुग्यो स्ट्रेन अपेक्षाकृत कम घातक माना जाता है, लेकिन इसमें भी 32 से 40 प्रतिशत तक मौतें दर्ज की गई हैं. कुछ मामलों में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक पहुंचा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, इलाज की उपलब्धता और संक्रमण की गंभीरता के आधार पर मृत्यु दर बदल सकती है.

जंगलों से फैलता है वायरस

रिपोर्ट के अनुसार डीआरसी के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में यह वायरस प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ जैसे जंगली जानवर इस वायरस के मुख्य स्रोत हो सकते हैं. यह वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर कई लोगों की जान ले सकता है.

शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे

ईबोला के सभी स्ट्रेन के लक्षण लगभग समान होते हैं. शुरुआत में मरीज को तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और थकान महसूस होती है. कुछ दिनों बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गले में खराश जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. बीमारी बढ़ने पर आंखों, मसूड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों से खून बहने लगता है. कई मामलों में शरीर पर चोट जैसे निशान पड़ जाते हैं और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।

PM मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली। पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन की सरकार ने रविवार (17 मई, 2026) को अपने सर्वोच्च सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया है. यह किसी भी देश के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को अब तक कुल 31 अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो दुनिया के अलग-अलग देशों की तरफ से उन्हें दिए गए सर्वोच्च नागरिक और राजकीय सम्मानों में शामिल हैं. पीएम मोदी के स्वीडन दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को एक ज्यादा संगठित और तकनीक-आधारित आर्थिक साझेदारी में बदलना है।

फिर हारी पंजाब, धमाकेदार जीत से प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के 61वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया है. इस सीजन आरसीबी की यह 9वीं जीत है. पंजाब के खिलाफ जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहंचने वाली आरसीबी पहली टीम है. वहीं पंजाब किंग्स की यह इस सीजन छठी हार है. अब उनका प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है.

वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली के अर्धशतक से आरसीबी आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी. लगातार तीसरी जीत के साथ आरसीबी की टीम के 13 मैच में 18 अंक हो गए हैं और टीम टॉप पर बरकरार है. वहीं लगातार छठी हार के बाद पंजाब की टीम 13 मैच में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर है. अब उनके लिए प्लेऑफ में जगह बनाना काफी मुश्किल हो गया है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे. जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 199 रन ही बना सकी. पंजाब की हार से प्लेऑफ की रेस काफी दिलचस्प हो गई है. पंजाब की हार से चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स को बंपर फायदा हुआ है. इस मैच की बात करें तो आरसीबी की जीत में विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर और भुवनेश्वर कुमार का अहम रोल रहा. 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही. प्रियांश आर्य बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया. फिर उनके साथ प्रभसिमरन सिंह पांच गेंद में दो रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें भी भुवनेश्वर कुमार ने पवेलियन भेजा. इसके तुरंत बाद कप्तान श्रेयस अय्यर तीन गेंद में एक रन बनाकर चलते बने. उन्हें रसिख डार सलाम ने आउट किया.

19 रनों पर तीन विकेट गिरे तो अब मिडिल ऑर्डर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी. कूपर कोनोली ने 22 गेंद में 37 और सूर्यांश शेडगे ने 22 गेंद में 35 रनों की पारी खेली. वहीं मार्कस स्टोइनिस ने 25 गेंद में 37 रन बनाए, लेकिन जरूरी रन रेट के हिसाब से कोई भी नहीं खेल सका. पंजाब ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, जो हार का सबसे बड़ा कारण बना. पंजाब किंग्स के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंद में 56 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले, लेकिन वह सिर्फ हार के अंतर को ही कम कर सके. अजमतुल्लाह उमरजई 10 गेंद में 14 रनों पर नाबाद लौटे. लास्ट के ओवरों में पंजाब तेजी से रन नहीं बना सकी. आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 2 और रसिख डार सलाम ने तीन विकेट चटकाए।

दिल्ली ने राजस्थान को रुलाया टॉप-4 में जगह बनाना मुश्किल

नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है. इस जीत के साथ दिल्ली ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखा है. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए थे. जवाब में दिल्ली की टीम ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की.ध्रुव जुरेल और कप्तान रियान पराग के अर्धशतक और वैभव सूर्यवंशी की 46 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स 193 रनों तक पहुंची थी. दूसरी ओर दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया और 105 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी कर दिल्ली की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया.

प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल

दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत से प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल हो गया है. दिल्ली जो अधिकतम 14 अंकों तक जा सकती है और उसका क्वालीफिकेशन पूरी तरह अन्य टीमों पर निर्भर है. उसने राजस्थान का समीकरण भी बिगाड़ दिया है. राजस्थान और दिल्ली, दोनों के 12-12 पॉइंट्स हैं, लेकिन राजस्थान के 2 मैच बचे हैं और दिल्ली का सिर्फ एक. 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 105 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. राहुल ने 42 गेंद में 56 रन बनाए, वहीं पोरेल ने 31 गेंद में 51 रनों की पारी खेली. ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे खूंखार बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंद में 34 रन बनाकर दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा. विनिंग शॉट आशुतोष शर्मा के बल्ले से आया, जिन्होंने 5 गेंद में 18 रनों की कैमियो पारी खेली. दिल्ली की इस जीत में मिचेल स्टार्क का भी अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने राजस्थान के 4 बल्लेबाजों को आउट किया था. लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी ने भी घातक स्पेल फेंका।

वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल के नए सिक्सर किंग

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी अपने छोटे से आईपीएल करियर में ढेरों कीर्तिमान बना चुके हैं. यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि सूर्यवंशी ने अपने करियर में चौकों से ज्यादा सिक्स लगाए हैं. अब आईपीएल 2026 में उन्होंने छक्कों का एक महारिकॉर्ड बना दिया है. किसी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया है. किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब तक अभिषेक शर्मा के नाम था. अभिषेक ने आईपीएल 2024 में कुल 42 छक्के लगाए थे. मगर अब वैभव सूर्यवंशी उनसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 में अब तक उन्होंने 43 सिक्स लगा दिए हैं।

शूटिंग के लिए एमएस धोनी फिट IPL 2026 में इंजरी का बहाना?

नई दिल्ली। एमएस धोनी ने अब तक इंजरी के चलते IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक भी मैच नहीं खेला है. टीम ने 12 लीग मुकाबले खेल लिए हैं. अब सीएसके को अंतिम 2 मैच हैदराबाद और गुजरात के खिलाफ खेलने हैं. लेकिन इससे पहले धोनी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (NSG) के रीजनल हब पहुंचे, जहां उन्होंने शूटिंग में हिस्सा लिया. इससे एक सवाल तो खड़ा हो गया कि सीएसके फैंस को पागल बना रही है?

दरअसल चेन्नई ने 28 मार्च को धोनी को लेकर एक अपडेट शेयर करते हुए बताया कि काफ इंजरी के चलते वह शुरुआती 2 हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं. अब धीरे-धीरे 2 महीने होने वाले हैं और धोनी वापसी को लेकर कोई अपडेट नहीं है. लेकिन अगर धोनी अनफिट हैं, तो फिर वह एनएसजी के रीजनल हब में बिल्कुल ठीक तरह से रायफल के साथ शूटिंग करते हुए कैसे दिख रहे हैं? इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें धोनी अपनी फिटनेस के बारे में NSG कमांडो से पूछते हुए नजर आए।

आईपीएल के दौरान हो सकती है हार्दिक पांड्या की शादी

नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या मानिए अचानक IPL 2026 से गायब ही हो गए. सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए नियमित कप्तान की भूमिका निभा रहे हार्दिक ने पिछला मैच 02 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था, जिसको अब 15 दिन गुजर चुके हैं. इसी बीच हार्दिक की शादी को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया, जिसमें बताया गया कि वह आईपीएल के बीच ही दुल्हा बन सकते हैं. हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लंबे वक्त से एक दूसरे साथ देखा जा रहा है. आईपीएल के बीच में हार्दिक को माहिका के साथ देखा गया था. अब कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन के बीच ही हार्दिक और माहिका की शादी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. बात दरअसल कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को लेकर दावे होने लगे कि वह 22 मई को राजस्थान के उदयपुर में माहिका शर्मा के साथ एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे. एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अचानक हार्दिक और माहिका की शादी को लेकर बात क्यों होने लगी?

विदेशी कंपनी ने निकाला तोड़, फॉर्मूला भी बताया

अब पेट्रोल-डीजल नहीं, 'पानी' से चलेंगी गाड़ियां

नई दिल्ली। वैश्विक तेल संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच एक विदेशी कंपनी ने ऐसा दावा किया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. मोनाको की कंपनी FOWE Eco Solutions ने एक ऐसी तकनीक पेश करने का दावा किया है, जिसकी मदद से गाड़ियां और औद्योगिक मशीनें कम ईंधन में ज्यादा काम कर सकती हैं. कंपनी का कहना है कि इस तकनीक में पानी का इस्तेमाल करके ईंधन की खपत 10% तक कम की जा सकती है.यह प्रस्ताव भारत के लिए एक नाजुक समय में आया है, जब देश अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में ईंधन बचाने वाली किसी भी तकनीक का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और रुपये पर पड़ता है. इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ईंधन बचाने पर जोर दे चुके हैं.

कैसे काम करती है यह तकनीक?

कंपनी के मुताबिक, उसकी पेटेंट तकनीक "कैविटेक फ्यूल इमल्शन" ईंधन और पानी को खास तरीके से मिलाती है. इससे ईंधन के अंदर पानी की बेहद छोटी बूंदें बनती हैं, जो जलने के दौरान कण के अंदर "माइक्रो एक्सप्लोजन" पैदा करती हैं. इस प्रक्रिया से ईंधन ज्यादा बेहतर तरीके से जलता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और धुआं भी कम निकलता है. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस तकनीक के लिए इंजन में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही इसका इस्तेमाल बिना मशीन बंद किए हुए भी किया जा सकता है.

ईंधन बचत और प्रदूषण घटाने का दावा

कंपनी और स्वतंत्र परीक्षण आंकड़ों के मुताबिक, इस तकनीक से बॉयलर और समुद्री इंजनों में 6-10% तक ईंधन बचत देखी गई है. भारत के कुछ रिफाइनरी और इस्पात संयंत्रों में भी परीक्षण किए गए, जिनमें ईंधन की बचत 3.6% से 6% तक दर्ज की गई.FOWE का कहना है कि इससे NOx और SOx जैसे हानिकारक उत्सर्जन में भी 40% तक कमी लाई जा सकती है. साथ ही बॉयलर और भट्टियों के अंदर गंदगी कम जमा होती है, जिससे रखरखाव का खर्च भी घट सकता है. हालांकि, यह तकनीक अभी बड़े स्तर पर आम वाहनों में इस्तेमाल नहीं हो रही है. फिलहाल इसका परीक्षण औद्योगिक इकाइयों, जहाजों और बिजली संयंत्रों में किया जा रहा है. वहीं, एक्सपर्टों का मानना है कि अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल साबित होती है, तो आने वाले दिनों में ईंधन बचत के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है.

आईटी सेक्टर में चार दिनों में 25000 लोगों की हुई छंटनी

नई दिल्ली। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों में इस समय छंटनी का दौर लगातार जारी है. साल 2026 में अब तक हजारों कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 के दो हफ्तों में ही करीब 25 हजार टेक कर्मचारियों की नौकरी चली गई. सबसे बड़ी बात ये है कि ज्यादातर कंपनियां अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं और इसी वजह से कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है. यहां से जानें वो कौन सी कंपनियां हैं, जो ले ऑफ कर रही हैं या कर चुकी हैं और छटनी का असली कारण क्या है, इसकी जानकारी भी यहां दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PayPal, Cisco और Cloudflare जैसी बड़ी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है. सबसे ज्यादा चर्चा PayPal की हो रही है. कंपनी अगले कुछ सालों में अपनी लगभग 20 प्रतिशत वर्कफोर्स कम करने की तैयारी में है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

अधिकारी पर भड़के बृजमोहन ग्रामीणों ने बजाई ताली

कहा- सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है, अभिनंदन करें कि क्या करें; सुशासन तिहार में फटकारा

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर के आरंग के नगर पंचायत समोदा में सुशासन तिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल शिकायत मिलने ही भड़क गए। उन्होंने नायब तहसीलदार गजानंद सिदार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि, आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। कितना पैसा लेते हो, जो लोगों को बोलते हो...क्या बोलते हो लोगों से? इसकी सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दिए हो सांसद जी को...कितना पैसा दिए हो? यह बातकर सुनकर वहां शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण ताली बजाने लगे। फटकार लगाते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, समोदा हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार (15 मई) को आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जनता की शिकायतें सुनना था, लेकिन मंच पर सबसे ज्यादा मुद्दा तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर उठा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि, समोदा तहसील कार्यालय में राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय पर नहीं हो रहा है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा समेत कई केस महीनों से लंबित पड़े हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि काम कराने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है और बिना लेन-देन के फाइलें आगे नहीं बढ़तीं।

'कितना पैसा दिए हो सांसद जी को?' ... मंच से भड़के बृजमोहन

बृजमोहन: यहां के नायब तहसीलदार कौन हैं जी?

(समोदा में पदस्थ नायब तहसीलदार गजानंद सिदार को मंच पर बुलाया)

बृजमोहन: आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ... सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। कितना पैसा लेते हो, जो लोगों को बोलते हो... क्या बोलते हो लोगों से? इसकी सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दिए हो सांसद जी को... कितना पैसा दिए हो?

गजानंद सिदार: (हाथ के इशारे से इनकार करते हैं)

बृजमोहन: ये मेरे पास आवेदन है। इसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? बताओ मुझे

बृजमोहन: एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम साहब, यहां की जनता की सबसे ज्यादा शिकायत नायब तहसीलदार की है। जरा देखिए इसके पास कितने केस पेंडिंग हैं। उसका रिव्यू करो और जल्द निराकरण होना चाहिए। ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। इन दोनों प्रकरणों की रिपोर्ट बनाकर 3 दिन के भीतर मुझे भेजिए। और भविष्य में मेरे पास आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी ही आ रही है।

भूपेश बोले-जनता से अपील कर PM विदेश यात्रा पर निकले

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल-डीजल बचाने को लेकर पीएम मोदी की अपील पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि, भाजपा का काम ही "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" वाला है। पीएम जनता से पेट्रोल बचाने की बात करते हैं और खुद विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। भूपेश ने कहा कि सरकार खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और जनता को पालन करने की नसीहत दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों से आने वाला क्रूड ऑयल दूसरे देशों को भेजा जा रहा है, जबकि देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के हालात बन रहे हैं। इधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को सिर्फ जरूरी कामों पर खर्च करने और फिजूलखर्ची रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडल के अधिकारियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की जाएगी। ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को अब मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी और सिर्फ जरूरी होने पर ही विदेश दौरे मंजूर होंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में वाहन पूलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, ट्रैफिक कम होगा और सरकारी खर्च में कटौती होगी। ये निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे और सभी विभागों के लिए इनका पालन अनिवार्य होगा। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाले IGOT कर्मयोगी पोर्टल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है।

पीसीसी चीफ ने कसा तंज, पीएम की नहीं सुनते गृहमंत्री शाह

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश से आह्वान कर रहे है कि वर्कफ्राम होम करे पेट्रोल-डीजल बचाये, उनके ही गृहमंत्री मुख्यमंत्री उनकी बात का माखौल उड़ा रहे, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक वर्चुअल क्यों नहीं किया जबकि सभी मुख्यमंत्री सचिवालय तथा गृह मंत्रालय के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चार राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि बस्तर आयेंगे। सब अलग-अलग विशेष विमान से आयेंगे, लाखों रू. खर्च होगा, डीजल-पेट्रोल तथा विमान का ईंधन खर्च होगा। यह बैठक तो वर्चुअल हो सकती।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक बस्तर में बुलाना भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक के दावा किया था, 31 मार्च के बाद नक्सलवाद समाप्त हो गया है। कांकेर में पिछले हफ्ते हमारे 4 जवान शहीद हुये, वीर गति को प्राप्त हुये। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनैतिक प्रोपोगंडा करना बंद नहीं की है। मध्यक्षेत्र की बैठक पहली बार बस्तर में करवाने पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मध्यक्षेत्र परिषद की बैठक बस्तर ले जाकर साबित करना चाहते है हमने यहां पर सारी चीजे सही कर दिया है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पिछले हफ्ते हमारे 4 जवान शहीद हुये है।

मध्यक्षेत्र की बैठक को बस्तर में करने का दूसरा उद्देश्य है कि वहां पर अडानी के लिये रेड कॉरपोरेट बिछाना चाहते है। वहां पर बैठक करने सरकार का मूल उद्देश्य है कि अपना पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करना और अडानी के आर्थिक हितों का संवर्धन करना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शाह बताये बस्तर के लिए कुछ विशेष पैकेज लेकर आये है या इस बार भी खाली हाथ आने वाले है। डबल इंजन की सरकार में बस्तर के विकास, बस्तर में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार 50 हजार करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा कब करेगी?

उर्वरक की कमी से खरीफ के सीजन में संकट आने वाला है - कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश में अभी तक उर्वरको का पर्याप्त भंडारण नहीं होने से खरीफ के सीजन में संकट आने वाला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उर्वरको की उपलब्धता पर सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। सभी समाचार पत्र खबरे छप रहे कि खरीफ सीजन के पहले उर्वरकों की कमी होने वाली है, लेकिन सरकार इस विषय पर कोई भी ठोस बात किसानों के सामने नहीं रख रही है। इसमें किसान परेशान है। पिछले वर्ष उर्वरकों की कमी को झेल चुके किसान सरकार के मौन के कारण विचलित हो रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कुल 2058 सहकारी समितियां है, जिनकी भंडारण क्षमता 4,84,665 मीट्रिक टन है। वहीं खरीफ सीजन के लिये कुल लक्ष्य 15 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक लगभग 51000 मीट्रिक टन उर्वरक का ही भंडारण हो सका है, जो लक्ष्य का मात्र 35.95 प्रतिशत है। यह स्थिति बताती है कि यदि आपूर्ति की गति नहीं बढ़ी तो खरीफ सीजन में संकट गहरा सकता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में डीएपी का भंडारण लक्ष्य 2,25,650 मीट्रिक टन तय किया गया है। जबकि अब तक सिर्फ 25 प्रतिशत भंडारण हो पाया है। कई जिलों में अब तक भंडारण शुरू ही नहीं हो पाया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई जिले इस मामले में सबसे पीछे है।

पार्टी के भीतर समर्थन और सुझावों में आने लगे नेता

जनचौपाल में कांग्रेस विधायक को रोकने वाले कलेक्टर एसपी पर हो कार्यवाही की मांग

शहर सत्ता/रायपुर। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंस को मुख्यमंत्री के जनचौपाल कार्यक्रम में जाने से रोकने वाले कलेक्टर एसपी पर कार्यवाही की मांग करते हुऐ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की नारी वंदन की ढोंग औऱ आधी आबादी को उसका हक़ देने की दावों की पोल खुल गई जब कांग्रेस के महिला विधायक शेषराज हरवंस को उनके पॉमगढ़ विधानसभाके ग्राम कोसला के जनचौपाल में जाने से कलेक्टर एसपी के द्वारा रोक दिया गया।

क्या भाजपा सरकार में महिला जनप्रतिनिधि का यही सम्मान है?इसी को महिला सशक्तिकरण कहते है?महिला विधायक को जनता के प्रति कर्तव्य निभाने से क्यों रोका गया? कलेक्टर एसपी को जनचौपाल में महिला विधायक को आने से रोकने किसने निर्देश दिया? ये कैसा गोपनीय जनचौपाल है?जिला प्रशासन आखिर क्या छुपाना चाहती थी?जनचौपाल का मतलब खुली चर्चा होती है जब जनप्रतिनिधि को रोका गया ऐसे में जनता की क्या खाक सुनी जायेगी?आखिर इतना डर किस बात का?महिला विधायक को जनचौपाल में जाने से रोकने वाले कलेक्टर एसपी पर कड़ी कार्यवाही हो.सरकार सुनिश्चित करे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल में लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। सरकार में बैठे लोगो की आलोचना सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। ढाई साल में सरकार के प्रति हर वर्ग में भारी नाराजगी है। सरकार पूरी तरह फैल हो गई है। सनस्याओ का अंबार लग गया है। जनता के गुस्सा से बचने हर तरफ सिर्फ तानाशाही चलाई जा रही है। प्रशासनिक अराजकता चरम सीमा में है सरकार का नियंत्रण प्रशासन में नही है।

जनता अपनी समस्याओं को लेकर विभागों का चक्कर लगा रही है। सरकार तिहार जन चौपाल का आयोजन प्रोपोगंडा करने कर रही है। इन आयोजनों में भी जनता को राहत नही मिल रहा है विपक्ष के जनप्रतिनिधि जब जनता की आवाज उठाते है तो उन्हें सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रोका जाता है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की जाती है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भाजपा सरकार के तानाशाही से डरने वाले नही है जनता की आवाज उठाते रहेंगे।

सुशासन तिहार : धमतरी को मिली 465 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

सुशासन तिहार बना जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और संवेदनशील प्रशासन का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों को 465 करोड़ रुपये की लागत के 102 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने 423 करोड़ 52 लाख 56 हजार रुपये लागत के 52 कार्यों का भूमिपूजन तथा 41 करोड़ 50 लाख 48 हजार रुपये से अधिक लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों के माध्यम से जिले में सड़क, पेयजल, नगरीय अधोसंरचना और जनसुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित समाधान की कार्यसंस्कृति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 1 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव में क्लस्टरवार शिविर लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एवं बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर संभाग में सुशासन तिहार के साथ "बस्तर मुन्ने" और "नियद नेल्लानार 2.0" अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने "मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान" का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं तथा जरूरतमंदों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जनसहभागिता का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी सौंपकर लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर "ड्रीम कॉरिडोर" वीडियो एवं "मां अभियान" की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन धमतरी एवं लर्निंग जॉय बेंगलुरु के मध्य एमओयू किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धमतरीवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दीं। उन्होंने अम्बेडकर चौक धमतरी से रूद्री चौक तक फोरलेन सड़क निर्माण, धमतरी में पेयजल हेतु इंटेकवेल निर्माण, रानी दुर्गावती चौक से बिलाईमाता मंदिर तक गौरवपथ निर्माण, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरूद भवन के लिए डेढ़ करोड़ रुपये तथा पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सांसद महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद श्री अजय चन्द्राकर, विधायक धमतरी श्री ओंकार साहू, महापौर श्री रामू रोहरा, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार आदि उपस्थित थे।

सुशासन तिहार में साकार हुआ पक्के घर का सपना

"अपना पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और नए जीवन की मजबूत नींव होता है।" धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के दौरान यह भाव उस समय जीवंत हो उठा, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपकर उनके वर्षों पुराने सपनों को साकार किया। सुशासन तिहार में भाटगांव की हितग्राही श्रीमती कुमारी यादव एवं श्रीमती लता साहू को मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों आवास की चाबी प्रदान की गई। वर्षों तक कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने वाले इन परिवारों के लिए यह क्षण केवल एक सरकारी योजना का लाभ मिलने भर का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व से भरे नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। हितग्राही श्रीमती कुमारी यादव ने बताया कि बरसात के दिनों में उनका परिवार लगातार परेशानियों का सामना करता था। कच्चे घर की टपकती छत और कमजोर दीवारों के कारण बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सुरक्षा हमेशा चिंता का विषय बनी रहती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने से अब उनका परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है और बच्चों के भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगी है।

ग्रामीण अंचल की बेटी बनी प्रेरण, मुख्यमंत्री ने सराहा

धमतरी जिले के छोटे से ग्राम कंडेल की बेटी कुमारी कुसुम लता बिप्रे ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प से पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 97.40 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पांचवां स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल धमतरी जिले का गौरव बढ़ाया है, बल्कि ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल भी प्रस्तुत की है। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कुसुम लता को मंच पर सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा आगे की पढ़ाई और तकनीकी शिक्षा में सहयोग के उद्देश्य से टैबलेट प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज शिक्षा, खेल, विज्ञान और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और राज्य सरकार उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रही ऐसी प्रतिभाएं विकसित छत्तीसगढ़ की नई पहचान हैं और सरकार प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुसुम लता की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था, परिवार के संस्कार और विद्यार्थियों की मेहनत का सकारात्मक परिणाम है।

धरमजयगढ़ के गंवरघुटरी में बनेगा 100 बिस्तरों का अस्पताल

रायगढ़ जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम गंवरघुटरी अब स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल और राज्य शासन की जनकल्याणकारी सोच के परिणामस्वरूप यहां 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण से धरमजयगढ़ सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों, विशेष रूप से आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम गंवरघुटरी, तहसील धरमजयगढ़ की 2 हेक्टेयर भूमि 30 वर्ष की अस्थायी लीज पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को आबंटित की गई है। इस भूमि पर फाउंडेशन द्वारा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर संभाग के जांजगीर-चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिलों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भूमि आबंटन आदेश की प्रति सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है।

अनुष्का शेट्टी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

मुंबई। साउथ की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दर्शक और समीक्षक दोनों ही अनुष्का की दमदार अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच अनुष्का शेट्टी ने अपने प्रशंसकों को चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा की है। इस खबर ने उनके चाहने वालों को निराश कर दिया है।

अनुष्का ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट साझा करते हुए लिखा – "नीली रोशनी को मोमबत्ती की रोशनी में बदल रही हूं। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहूंगी। बस दुनिया से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हूं। स्क्रॉलिंग के अलावा उस जीवन में लौटना चाहती हूं, जहां से हम सबने शुरुआत की थी।"

फैंस की प्रतिक्रिया

अनुष्का शेट्टी का यह पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई प्रशंसकों ने उनकी भलाई की कामना की और जल्द वापसी की उम्मीद जताई। वहीं कुछ प्रशंसक निराश भी दिखे कि अपनी पसंदीदा अभिनेत्री से जुड़ी अपडेट्स अब कुछ समय तक नहीं मिलेंगी।

फिल्मों में व्यस्त कार्यक्रम

अनुष्का शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री हैं और 'बाहुबली' जैसी सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने खास पहचान बनाई है। उनकी हालिया फिल्म 'घाटी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। माना जा रहा है कि वे जल्द ही अपनी आने वाली परियोजनाओं की तैयारी में भी व्यस्त होंगी।

'वायुपुत्र' होगी चंदू मुंडेटी की आगामी उडी एनिमेशन फिल्म

निर्देशक चंदू मुंडेटी की नई उडी एनिमेशन फिल्म का नाम 'वायुपुत्र' है। यह फिल्म दशहरा 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म को लेकर सेलेब्स और फैंस ने चंदू को शुभकामनाएं दी हैं। चंदू ने सोशल मीडिया पर 'वायुपुत्र' का पहला पोस्टर साझा किया और इसे अपने बचपन का सपना बताया है। साथ ही उन्होंने भगवान राम, हनुमान, ऋषि वाल्मीकि और अपने परिवार को धन्यवाद दिया। इस पोस्टर में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान की तस्वीर साफ नजर आ रही है। वह पीठ घुमाए खड़े हैं और पूरा दृश्य आग की लपटों की वजह से और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा है। पोस्टर में हनुमान को एक पहाड़ पर खड़े दिखाया गया है, जो लंका को जलते देख रहे हैं। इस पोस्ट के साथ चंदू ने कैप्शन में लिखा, 'वायुपुत्र सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पवित्र तमाशा। इस कहानी को बताने के लिए तैयार, हमारे इतिहास की आत्मा, हमारे इतिहास के पन्ने एक बचपन का सपना। भगवान श्रीराम, भगवान हनुमान, ऋषि वाल्मीकि, मेरे परिवार का धन्यवाद, गरु का धन्यवाद। जयश्रीराम। जयहनुमान।'

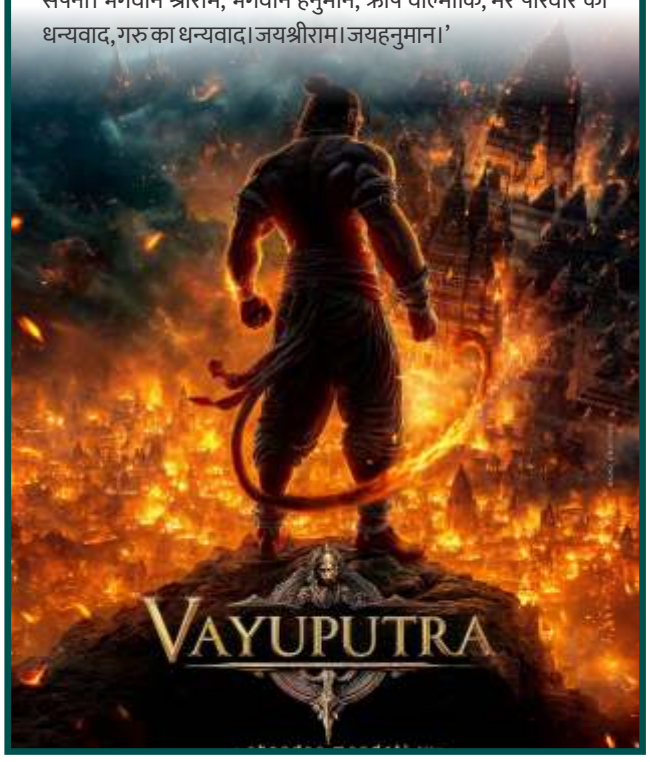

इंटरनेट हमें मंदबुद्धि बना रहा है: नवाजुद्दीन

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वे अपने शुरुआती दिनों में बिना ब्रेक लिए एक ही दिन में तीन-तीन प्ले की रिहर्सल किया करते थे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे समय पर इंटरनेट नहीं था और हमारे पास बहुत सारा समय होता था. उस वक्त हमारा सारा फोकस हमारे काम पर होता था और हम एक दिन में तीन-तीन प्ले की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज सबके पास फोन है और अभी जानकारी के तौर पर एक्टिंग के मेथड्स के बारे में पता है, लेकिन आज एक्टर्स के पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं है. न्होंने कहा कि इंटरनेट की वजह से याददाश्त पर बहुत फर्क पड़ रहा है और ये हमें डम्बो बना रहा है. मान लें कि हमने 100 से ज्यादा किरदार किए हैं और दोबारा वैसा ही किरदार मिलने पर हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है. काम के बीच में 5 मिनट फोन देखने के बाद कुछ देर बाद ये याद नहीं रहता कि क्या देखा था. बता दें, 'मैं एक्टर नहीं हूं' फिल्म एक ऐसी कहानी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पेशे से बैंकर हैं लेकिन महत्वाकांक्षा अभिनेता बनने की है. फिल्म में वे अपने कौशल को निखारने और अपने अभिनेता बनने के अपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।

हिट हीरोइनों की फ्लॉप बहनें

बॉलीवुड की हिट हीरोइनों की चमक-धमक तो सब देखते हैं, लेकिन उनकी फ्लॉप बहनों की जिंदगी अक्सर अनकही रहती है. किसी ने अमीर बिजनेसमैन से शादी कर शानदार जिंदगी बनाई, तो कुछ अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रही हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे नाम.

मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा

अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा की बहन हैं और उन्होंने बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की. उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन मलाइका की तरह बड़ी सफलता नहीं पा सकीं. उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया. इसके बाद अमृता ने एक्टिंग की बजाय निजी जिंदगी और अन्य पेशों पर ध्यान दिया. अमृता अरोड़ा ने अमीर बिजनेसमैन शकील लदाक शादी की है. शादी के बाद वह पर्सनल लाइफ में शांत और मीडिया से दूर रहने लगीं.

काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी

काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में की थी. उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग किया, लेकिन काजोल की तरह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाईं. तनीषा ने मुख्य रूप से रोमांटिक और ड्रामा फिल्में कीं, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का रिएक्शन मिस्ड रहा. उनकी तुलना अक्सर बड़ी बहन काजोल से की जाती रही, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ा. हालांकि, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी. वर्तमान में तनीषा फिल्मी दुनिया से दूर हैं।

शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी

शमिता शेट्टी, बॉलीवुड एक्ट्रेस और शिल्पा शेट्टी की बहन हैं. उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन शिल्पा की तरह बड़ी सफलता नहीं पा सकीं. शमिता ने कुछ फिल्में की, लेकिन उनमें खास कमर्शियल हिट नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने टीवी रियलिटी शोज़ और डांस प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रहकर अपनी पहचान बनाई. वर्तमान में शमिता फिल्म इंडस्ट्री और टीवी दोनों में धीरे-धीरे काम कर रही हैं. उन्हें बिग बॉस में देखा गया था.

मानवीय जीवन के आदर्श की अभिव्यक्ति है कारी

डॉ. संतराम देशमुख

छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य कारी आंचलिक संस्कृति और मानवीय जीवन के आदशों की अभिव्यक्ति है। कारी दुख सुख की ऐसी किताब है जिसमें हर शब्द में प्रेम, हर पंक्ति में दया और वाक्यों में करुणा का दर्शन है, मातृत्व का उमड़ता सागर है तो उनके प्रत्येक पृष्ठ पर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय भी है। शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, भारतीय नारी की प्रतिनिधि है कारी।

संस्कृति और पुरूष प्रधान समाज में गिरफ्त नारी को उबारने का आह्वान है। छत्तीसगढ़ी परम्परा में विधवा होने के बाद चूड़ी पहनने की प्रथा को तोड़ कर परम्परा को एक नया मोड़ दिया है, जिससे जीवन शैली में एक नई क्रांति आई है जो सराहनीय है। कारी का विवादग्रस्त अभिनय लोगों के मन का आकर्षण है। कारी गांव की अबूझ भोली भाली नारी का प्रतीक है। कारी के विधवा होने का दृश्य देखने वालों की आंखों को नम कर देता है। कारी के दुख में सबको सहभागी बना देता है। संवाद में व्यंग्य के तीखे प्रहार का स्वर भी उभरा है। सचमुच छत्तीसगढ़ की नारी भूखी, अभावग्रस्त और अनपढ़ होते हुए भी सरल होती हैं। श्रम करती हैं और अपना जीवनयापन हर स्थिति में कर लेती हैं, उसके हृदय में प्रेम की गंगा सदा प्रवाहित होती रहती है। वह ममतादायिनी है। कारी के प्रदर्शन में संवाद प्रेम साइमन और निर्देशन राम हृदय तिवारी तथा कारी की भूमिका शैलजा ठाकुर ने की है। अन्य प्रमुख कलाकारों में कृष्ण कुमार चौबे, विजय मिश्रा, विनायक अग्रवाल, विसंभर यादव, ध्रुव सिंह, चतरु साहू, सुरेश यादव, नवल मानिकपुरी, भैया लाल हेड़ाऊ, गिरजा सिन्हा के अलावा अनेक बाल कलाकारों ने कारी के प्रदर्शन को जीवंत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कवधूरागढ़ और गोंडवाना समाज

वर्तमान में कवर्धा या कबीरधाम स्वतंत्र जिला बन चुका है। कवर्धा मैंकल श्रृंखलाओं में स्थित है। इसका प्राचीन नाम कवधूरागढ़ था। यहां नाग चिन्हधारी राजा भोरमदेव प्रथम राजा हुए, जो गढ़ मंडला के नाग गंडचिन्ह धारक नागदेव राजा का बड़ा भाई था। इनके वंशजों ने कवधूरागढ़ में मड़वा महल, छेरकी महल, खंडवा महल, छपरी महल के अतिरिक्त भोरमदेव नामक शंभू महादेव देवालय बनवाया। जिसका अवशेष अभी भी है। रंगेल सिंह द्वारा लिखित गणवीरों की गाथा में गढ़ मंडला के पोल सिंह नामक नाग गंडचिन्ह धारक उईकाल गोत्रिय राजा के तीन पुत्र थे। पोल सिंह के मरणोपरांत अपने पिता के राज्य को तीन संभावों में विभाजित किया। गढ़ मंडला, कवधूरागढ़ और पांचाल गढ़। यह वही कवधूरागढ़ है जहां भूरदेव के पश्चात ई पूर्व 385 से 800 तक वहां नलदेव, ओलिसुर, बारीसुरमुरपाल, मंगा सुर, वीर सिंह, भुर पाल, लमकापुर, मादो सिंह, जुगा दर, मालू कोमा, नाग मुरा, हर देव आदि बीस राजाओं का शासन था। नवीं शताब्दी में वहां अहिराज नामक नाग गंडचिन्ह धारक राजा सत्ता में आया। वहां प्राप्त शिलालेखों में अहिराज सज्जल, धारणी घर, महिम देव, सपन देव, गोपाल देव, भुवन के पाल, कीर्ति पाल, जगत पाल, महिपाल, छन्नू पाल, भुवन, कमल, भीमा देव, हरि पाल राजाओं ने नौवीं से तेरहवीं शताब्दी तक राज्य किया। बाद में गढ़ मंडला के राजा मदन सिंह अधिपत्य में आ गया। इस गढ़ के शासकों ने गोंडवाना समुदाय के देश काल, रुचि और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार निर्माण कार्य विकसित किया।

सबसे अधिक कार्य छठी पीढ़ी के राजा गोपाल देव एवं अंतिम राजा राम चंद्रा ने प्रचलित शैली एवं मान्यताओं को विकसित किया। भोरमदेव देवालय शम्भू महादेव जो गंड समुदाय के पंचखंड धरती के स्वामी और जीववादी जीवन शैली के प्रणेता थे, उनकी याद में भोरमदेव बनाया गया। जिसमें मंडला राजा रानी द्वारा बूढ़ा देव की आराधना करते हुए दिखाया गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में गज और उस पर सिंह वाला गोंडवाना राज चिन्ह अंकित है। यहां शैव एवं वैष्णव देवी देवता हैं, इसका मतलब उन्होंने सभी धर्मों को राजाश्रय दिया।

जल संग्रहित करने का कृत्रिम झील
दलपत सागर

डॉ. डी पी देशमुख

पानी के अंधाधुन दोहन से जमीनी स्तर पर जल का श्रोत निरंतर नीचे होता जा रहा है। भविष्य में यह जल संकट का स्पष्ट संकेत है, इसके लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तरह का प्रयास बरसाती सीजन में अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने का प्रयोग जगदलपुर में सैकड़ों वर्ष पूर्व से सबसे बड़े कृत्रिम झील 'दलपत सागर' का निर्माण जल संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक है। 17 वीं सदी में लगभग 400 वर्ष पूर्व बस्तर के तत्कालीन राजा दलपत राय कांकतीय ने 350 हेक्टेयर जमीन में वर्षा जल के संचयन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

यह कार्य जल संग्रहण के साथ ही प्रकृति संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक माना जाता है। वर्तमान समय में इस तरह के कार्यों की सार्थकता बढ़ जाती है। राजा ने बरसाती सीजन के अतिरिक्त जल के संचयन हेतु राजमहल के पास तीन तालाबों का उत्खनन करा कर उसे विशाल झील का स्वरूप दिया जो जगदलपुर शहर के बीचों बीच दलपत सागर के रूप में प्रसिद्ध है। इस विशाल झील में संग्रहित जल का उपयोग शहर के पेयजल, खेतों की सिंचाई, जनसामान्य के दिनचर्या के कार्य एवं मछली पालन जैसे विविध कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही पिकनिक स्पॉट के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस झील की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाने हेतु यहाँ पर प्रकाश स्तंभ, संगीतमय फव्वारा, झील के बीचों बीच कृत्रिम द्वीप, देवी काली मां मंदिर में जैसे धर्म-कर्म संबंधित कार्य होने से इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व बढ़ गया है। जनआस्था के अनुरूप दलपत सागर के सौंदर्याकरण, रख-रखाव एवं अन्य उपयोगी सुविधाओं को विकसित करने से इसकी प्रसिद्धि पर्यटन के अनुरूप होने से इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।

पेंडरा जमींदारी का भी अपना अलग महत्व रहा

पेंडरा जमींदारी का क्षेत्रफल 774 वर्ग मील था। इसमें 225 ग्राम थे। यहां के जमींदार अपने नाम के पूर्व लाल लगाते थे। कहा जाता है कि, कल्चुरी आश्रय में दो भाई थे-हिंदू सिंह और छिंदू सिंह। इन्हें एक सड़क के किनारे बोरा भर द्रव्य मिला। उन्होंने इसे कल्चुरी शासक को दे दिया। इस ईमानदारी का इनाम पेंडरा जमींदारी के रूप में दिया गया। इसके उपरांत उनकी 12 पीढ़ियां यहां जमींदार रहीं। आगे चलकर हिन्दू सिंह के वंशज, पेड़रा के उपरांत, केन्दा उपरोड़ा और मातिन की जमींदारिया पाने में भी सफल रहे। मराठों के आगमन के समय यह जमींदारिया हिंदू सिंह के वंशजों के पास थी। 1798 में मराठों की दृष्टि टेढ़ी हुई। इसके पूर्व मराठे, मुंगेली और नवागढ़ पर कुदृष्टि डाल चुके थे। अतः जब मराठा सूबा केशव पंत द्वारा जमींदार पृथ्वी सिंह को रतनपुर आने का बुलावा आया तो वह पहले ही आशंकित हो सचेत हो गया। वह नहीं गया। अतः सूबा केशव पंत ने जमींदारी जब्त कर ली। पृथ्वी तीर्थ यात्रा का निमित्त कर भाग गया। अब पेंडरा जमींदारी एक गोंड जमींदार को दी गई। 1804 में सुहागपुर जमींदार द्वारा पेंडरा पर आक्रमण कर दिया गया। गांव को जला दिया गया। तब भोंसला जमींदार धन सिंह ने डट कर मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को वापस भगा दिया। धन सिंह को इस वीरता पुरस्कार के स्वरूप पेंडरा की जमींदारी दी गई। 1818 में जब अंग्रेजसत्ता आई और एग्न्यु छत्तीसगढ़ का सुप्रिटेंडेंट बना तो धन सिंह के वंशज अजीत सिंह को दी गई थी। पेंडरा शब्द पिंडारी से बना।

- **कल्चुरी शासक की 12 पीढ़ियां यहां जमींदार रहीं**

दिग्गजों से हनीमून खत्म...

प्रदेश भाजपा संगठन के कोर ग्रुप से कद्दावर नेताओं की छुट्टी

- केन्द्रीय नेतृत्व के मिजाज, कार्यशैली की नजरों में दिग्गज पस्त
- भाजपा के ट्रबल शूटर बृजमोहन अग्रवाल की अनदेखी पड़ेगी भारी
- संगठन दे रहा सक्रिय राजनीति से रिटायर होने वालों को संकेत
- बृजमोहन अग्रवाल को छोड़कर शेष की सक्रियता पर उठ रहे सवाल

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 9424225829

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के अगले चुनाव के लिए करीब ढाई वर्ष शेष है। नये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2028 में होंगे। भाजपा की चुनाव तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश कार्य समिति व कोर कमेटी से कुछ पुराने वरिष्ठ सदस्यों को विदा कर नये व ऊर्जावान साथियों को शामिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय नेतृत्व चुनाव के पूर्व अपेक्षाकृत नयी टीम को मैदान में उतारना चाहता है. फिलहाल जो बदलाव हुए हैं , वे चुनाव में उजली संभावनाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस प्रक्रिया में विरोध व असंतोष की लहर का उठना स्वाभाविक है, पर फिलहाल उसकी गति मंद है।

शहर सत्ता/रायपुर। जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कई नेता नाराज हैं यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल भर से इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। साल भर के घटनाक्रम की बात करें तो वरिष्ठ, दिग्गज और कद्दावर पार्टी नेताओं से संगठन का सियासी हनीमून ख़त्म हो गया है। चर्चा है कि किसे किनारे लगाना है, किसे मंत्री बनाना है, किसे संगठन में बड़ा पद देना है सारा कुछ तय मोदी-शाह कर रहे हैं। चर्चा के बीच कांग्रेस ने भी तो आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कि डबल इंजन की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार को खड़ाऊ सरकार कह रहा है, तो कोई इसे रबड़ स्टैंप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नयी टीम में 14 मंत्री व 17 विधायकों को जगह दी गई है। विधान सभा में भाजपा विधायकों की कुल संख्या 54 है। केन्द्रीय नेतृत्व के मिजाज व कार्यशैली को देखते हुए यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है।

हालांकि कोर ग्रुप से सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल की ही नहीं अपितु रामविचार नेताम विक्रम उसेंडी रेणुका सिंह की भी छुट्टी हुई है। लेकिन अब कद्दावर माने जाने वाले नेता बृजमोहन अग्रवाल की कोर ग्रुप से छुट्टी उनकी राजनीतिक विरासत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। बृजमोहन अग्रवाल को जिस तरीके से सत्ता और संगठन किनारे करने की कोशिश में लगी रही और लगता है अब जाकर उन्हें कामयाबी मिली है। 15 साल रमन राज में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल विष्णुदेव साय सरकार में भी मंत्री बने उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन अचानक लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा और अपमान की खबर जमकर चर्चा में रही कांग्रेस ने भी खूब तंज कसा।

कोर ग्रुप से इनकी छुट्टी

कोर कमेटी से सात दिग्गज नेताओं पुन्नूलाल लाल मोहले, गौरीशंकर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह, रमन सिंह को बाहर कर दिया गया है. ये सभी अलग-अलग अवधि मे सरकार व संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके है।

भाजपा के ट्रबल शूटर बृजमोहन

रमन कार्यकाल से लेकर अब मोदी, शाह, साय और चौधरी तक उन्हें पार्टी का सियासी आतंकी मैंने की चर्चा है। फिर भी तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद बृजमोहन की राजनीतिक सेहत पर फर्क नहीं पड़ा है। उनकी राजनीतिक सक्रियता भी ना घटी और न ही लोकप्रियता कम हुई है। लेकिन बंगले से उनके नौ रत्न और मुलाकातियों की आमद रफ़्त जरूर कम होने लगी है। जननेता तब खासा बौरा जाता है जब उसके बंगले से भीड़ गायब होने लगे। पार्टी के केन्द्रीय प्रमुखों ने उन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर रखने का मन पक्का कर लिया था। उनकी अनिच्छा के बावजूद उन्हें रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से टिकिट दे दी गई। वे राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ चुनाव जीत गए। बृजमोहन सांसद जरूर बन गए हैं किन्तु प्रदेश की राजनीति में वैसे ही सक्रिय है जैसे विधायक व मंत्री रहते हुए थे। उनका मानना है कि विरोधी कितनी भी कोशिश कर लें, उनका कुछ नहीं बिगाड पाएंगे क्योंकि उनके पीछे जनता की ताकत है।

कोर ग्रुप में इनकी एंट्री

डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, लता उसेंडी व शिवरतन शर्मा को लिया गया है. प्रदेश कार्य समिति में भी बदलाव किया गया है. 23 विधायकों को सदस्य नहीं बनाया गया है। जबकि परंपरागत रूप से पार्टी के सभी विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य समिति में रहते हैं।

अनदेखी भारी न पड़ जाए

पार्टी को इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि बृजमोहन, रमन, रेणुका, अजय चंद्राकर, मूणत, रामविचार, रमेश बैस, पुन्नूलाल जैसे वरिष्ठ व अनुभवी नेता को किनारे करने से चुनाव में पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। बहरहाल कोर कमेटी व कार्य समिति से दिग्गज नेताओं को बाहर किए जाने के बाद सरकार व संगठन से नाराज असंतुष्टों की लंबी कतार बनती जा रही है. राज्य विधान सभा के अब तक के सत्रों में विष्णुदेव साय सरकार को दोहरे मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है. मुख्य विपक्ष कांग्रेस तो है ही, दूसरा उसका अपना प्रतिपक्ष है अर्थात अपनी ही सरकार से तल्ख सवाल करने वाले वे विधायक हैं जो असंतुष्ट खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कार्यकर्ता ही लगाएंगे बेड़ा पार

यदि कार्यकताओं की पूछ-परख नहीं होगी, सत्ता व संगठन में उन्हें सम्मान नहीं मिला, सरकार से संबंधित छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी उन्हें तरसाया गया तो जाहिर है असंतोष का लावा अंदर ही अंदर खदबदाता रहेगा और अवसर मिलते ही बाहर आ जाएगा. बीते ढाई वर्ष में साय सरकार व संगठन के कामकाज से ऐसी स्थिति धीरे-धीरे बनती जा रही है.

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27